

## Weekly One Liners 15<sup>th</sup> to 21<sup>st</sup> June, 2026

### QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027: भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंचा

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने दुनिया भर में पांचवां स्थान हासिल किया है और लिस्ट में लगभग 52वें स्थान पर है। यह देश के बढ़ते एकेडमिक प्रभाव, बढ़ती रिसर्च क्षमताओं को दिखाता है और इससे दुनिया भर में नाम बेहतर होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली दुनिया भर में 118वें स्थान पर सबसे ऊंची रैंक वाला भारतीय संस्थान बनकर उभरा है, जो भारतीय टीम में सबसे आगे है।

### QS रैंकिंग में भारत की अब तक की सबसे मज़बूत मौजूदगी

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 ने 106 देशों के 1,500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन को इवैल्यूएट किया है, जो इसे हायर एजुकेशन के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल असेसमेंट में से एक बनाता है।

साथ ही, पिछले कुछ सालों में भारत का रिप्रेजेंटेशन काफी बढ़ा है। 2017 एडिशन में सिर्फ़ 14 इंस्टीट्यूशन से, देश में अब 2027 में 52 रैंक वाली यूनिवर्सिटी हैं, जो एक दशक में 271 परसेंट की शानदार बढ़ोतरी है।

इस उपलब्धि से भारत सिर्फ़ इन देशों से पीछे है,

- संयुक्त राज्य अमेरिका (184 संस्थान)
- यूनाइटेड किंगडम (93 संस्थान)
- चीन (85 संस्थान)
- जर्मनी (60 संस्थान)

भारत अब दुनिया में पाँचवें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वाले हायर एजुकेशन सिस्टम के तौर पर रैंक करता है।

### IIT दिल्ली भारत का टॉप रैंक वाला इंस्टीट्यूशन बना

भारतीय संस्थानों में, IIT दिल्ली ने दुनिया भर में 118वीं रैंक हासिल की है। इंस्टीट्यूट ने भारत की लीडिंग यूनिवर्सिटी का अपना स्टेटस बनाए रखा और QS रैंकिंग में किसी भारतीय इंस्टीट्यूशन की अब तक की सबसे अच्छी ग्लोबल रैंकिंग के बराबर पहुंच गया।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले भारतीय संस्थानों में शामिल हैं,

- आईआईटी दिल्ली
- आईआईटी बॉम्बे
- आईआईटी मद्रास
- आईआईटी खड़गपुर
- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)

ये इंस्टीट्यूशन टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्री एंगेजमेंट जैसे एरिया में एक्सलेंस के ज़रिए इंडिया की ग्लोबल एकेडमिक रेप्यूटेशन को मज़बूत कर रहे हैं।

### QS रैंकिंग 2027 में टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़

ग्लोबल रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के इंस्टीट्यूशन का दबदबा बना हुआ है।

दुनिया भर के टॉप 20 विश्वविद्यालय

रैंक	विश्वविद्यालय	देश
1	मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एमआईटी)	संयुक्त राज्य अमेरिका
2	स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
3	इम्पीरियल कॉलेज	लंदन, यूनाइटेड किंगडम
4	ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय	यूनाइटेड किंगडम
5	विदेश महाविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
6	कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय	यूनाइटेड किंगडम
7	कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (कैलटेक)	संयुक्त राज्य अमेरिका
8	UCL	यूनाइटेड किंगडम
8	ETH	ज्यूरिख, ETH
10	सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (NUS)	सिंगापुर
11	हांगकांग विश्वविद्यालय	हांगकांग एसएआर
12	नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU)	सिंगापुर
13	पेकिंग विश्वविद्यालय	चीन
14	सिंधुआ विश्वविद्यालय	चीन
15	पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
16	येल विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
16	कॉर्नेल विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
18	चीनी विश्वविद्यालय, हांग कांग	हांगकांग एसएआर
19	यूएनएसडब्ल्यू	सिडनी, ऑस्ट्रेलिया
20	जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय	संयुक्त राज्य अमेरिका
20	यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, बर्केले	संयुक्त राज्य अमेरिका

यह रैंकिंग एशियाई यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ती ताकत को भी दिखाती है, खासकर सिंगापुर, चीन, हांगकांग, साउथ कोरिया और जापान की।

### भारत की बढ़ती अनुसंधान शक्ति

रैंकिंग की सबसे खास बातों में से एक भारत की बढ़ती रिसर्च परफॉर्मंस है।

QS के अनुसार, भारत के पास अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिसर्च आउटपुट बेस है, जो साइंटिफिक पब्लिकेशन और एकेडमिक योगदान में हुई बड़ी बढ़ोतरी को दिखाता है।

अनुसंधान उपलब्धियाँ

- प्रति फैकल्टी साइटेशन के मामले में ग्यारह भारतीय यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शामिल हैं।
- भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर फील्ड में अपनी ग्लोबल रिसर्च का दायरा बढ़ा रहा है।
- एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सरकार के बीच बढ़ते सहयोग से इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है।

### एम्प्लॉयर की साख में मजबूत प्रदर्शन

भारतीय संस्थान भी दुनिया भर के एम्प्लॉयर्स के बीच पहचान बना रहे हैं।

QS रैंकिंग से पता चलता है कि,

एम्प्लॉयर रेप्युटेशन के लिए दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में छह भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

यह मेट्रिक यह मापता है कि एम्प्लॉयर अलग-अलग इंडस्ट्रीयून से ग्रेजुएट को कैसे देखते हैं और यह इंडियन हायर एजुकेशन की क्वालिटी में इंडस्ट्री के भरोसे को दिखाता है।

एम्प्लॉयर की अच्छी रेप्युटेशन बहुत ज़रूरी होती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ढूँढ रहे हैं जो बेहतर करियर के मौके और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट देती हों।

### भारत की तुलना दूसरे बड़े एजुकेशन सिस्टम से कैसे की जाती है

कई स्थापित हायर एजुकेशन सिस्टम से तुलना की जाती है तो भारत का सुधार रेट सबसे अलग दिखता है।

प्रदर्शन तुलना

देश की रैंकिंग	संस्थानों में सुधार
चीन	85 72%
भारत	52 52%
यूके	93 35%
जर्मनी	60 16%
यूएसए	184 13%

जबकि अमेरिका और जर्मनी में कई संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है, भारत ने बड़े एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा सुधार दर दर्ज की है।

### भारत के उदय के कारक

QS ने भारत की तरक्की का श्रेय कई खास वजहों को दिया।

भारत में दुनिया की सबसे युवा आबादी है, जिससे हायर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा मांग है।

बढ़े हुए एनरोलमेंट और हायर एजुकेशन तक आसान पहुंच ने देश के एकेडमिक इकोसिस्टम को मजबूत किया है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 जैसी पहलों ने भी इंस्टीट्यूशनल सुधारों, इंटरनेशनलाइज़ेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग और रिसर्च में बेहतरीन काम को बढ़ावा दिया है।

भारतीय संस्थान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ तेज़ी से पार्टनरशिप कर रहे हैं जिससे एकेडमिक क्वालिटी और रिसर्च का असर बढ़ेगा।

### PM मोदी का ऐतिहासिक स्लोवाकिया दौरा: भारत और स्लोवाकिया ने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाया

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बुलावे पर 15 जून 2026 को स्लोवाकिया का ऐतिहासिक स्टेट विज़िट किया। यह विज़िट एक अहम पड़ाव था क्योंकि 1993 में देश को आज़ादी मिलने के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला विज़िट था। इस विज़िट ने भारत-स्लोवाकिया रिश्तों में एक नया चैप्टर खोला, जिससे दोनों देशों के रिश्ते एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक बढ़े और डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, लेबर मोबिलिटी, कल्चर, हेल्थकेयर और रिसर्च में कई एग्रीमेंट पर साइन हुए।

### भारत और स्लोवाकिया ने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाया

इस दौरे का एक सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों के रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फैसला हुआ।

इस नए फ्रेमवर्क का मकसद स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल सेक्टर में सहयोग को गहरा करना है।

दोनों देश मौजूदा सहयोग के तरीकों को मजबूत करने और नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सिक्योरिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में सहयोग के नए मौके तलाशने पर सहमत हुए हैं।

यह कदम आपसी विश्वास और लंबे समय के जुड़ाव के लिए एक साझा नज़रिए को दिखाता है।

**Test Prime**

**ALL EXAMS ONE SUBSCRIPTION**

**यात्रा के दौरान साइन किए गए मुख्य समझौते**

भारत और स्लोवाकिया ने अलग-अलग सेक्टर्स को कवर करने वाले 11 जरूरी एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम पर साइन किए हैं।

इन एग्रीमेंट्स में लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन और रिसर्च, ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन, डिफेंस कोऑपरेशन, क्रांटम कम्युनिकेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन में सहयोग शामिल है।

एक बड़ी बात यह हुई कि कोसिसे की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहली ICCR चेयर बनाई गई, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एकेडमिक सहयोग पर बढ़ते फोकस को दिखाता है।

पिएस्तानी के बीच सहयोग, साथ ही स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलरशिप और जॉइंट रिसर्च के लिए IIT दिल्ली और स्लोवाक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच पार्टनरशिप शामिल हैं।

**दोनों देशों के बीच हुए समझौते और समझौता ज्ञापन**

एस.नं.	समझौता/पहल
1	श्रम प्रवास पर समझौता ज्ञापन
2	रक्षा सहयोग पर आशय पत्र
3	डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर समझौता ज्ञापन
4	उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर समझौता ज्ञापन
5	ऑडियो-विजुअल निर्माण पर समझौता ज्ञापन
6	कोसिसे तकनीकी विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ICCR चेयर
7	क्रांटम संचार और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन
8	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ नेचुरोपैथी और स्लोवाक हेल्थ स्पा पिएस्तानी के बीच समझौता ज्ञापन
9	आईआईटी दिल्ली-स्लोवाक तकनीकी विश्वविद्यालय सहयोग समझौता
10	टूर ऑपरेटर्स के बीच पर्यटन सहयोग
11	INSA और SAS के बीच वैज्ञानिक सहयोग

**यात्रा के दौरान प्रमुख घोषणाएं**

PM मोदी के दौरे के दौरान तीन बड़ी डिप्लोमैटिक घोषणाएं भी की गईं।

घोषणा घोषणा	महत्व
द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाना	विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग का विस्तार
आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना	सुरक्षा सहयोग बढ़ाता है

घोषणा घोषणा	महत्व
कांसुलरी वार्ता की स्थापना	लोगों से लोगों के बीच और कूटनीतिक जुड़ाव में सुधार

**प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला**

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 जून 2026 को ब्रातिस्लावा की अपनी पहली ऑफिशियल यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान, यानी द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड पीटर पेलेग्रिनी ने भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मोदी के योगदान के लिए दिया।

**प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान मिला**

ब्रातिस्लावा में एक सेरेमोनियल इवेंट के दौरान, प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित किया, जो स्लोवाकिया की तरफ से विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिविलियन और मिलिट्री स्टेट डेकोरेशन है। आभार जताते हुए, PM मोदी ने यह अवॉर्ड भारत के लोगों को समर्पित किया और इसे भारत और स्लोवाकिया के बीच पक्की दोस्ती का प्रतीक बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहचान दोनों देशों के बीच प्यार, भरोसे और आपसी सम्मान को दिखाती है।

**ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस क्या है?**

ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया का सबसे बड़ा नेशनल अवॉर्ड है जो सिर्फ विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। यह सम्मान उन जाने-माने लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्लोवाकिया और दूसरे देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी समझ को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है। यह सम्मान मिलने से PM मोदी उन चुनिंदा ग्लोबल लीडर्स के ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिन्हें स्लोवाकिया ने उनके डिप्लोमैटिक योगदान के लिए मान्यता दी है।

**पुरस्कार का महत्व**

यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी दूसरे देश से मिला 33वां इंटरनेशनल सम्मान है, जो भारत के बढ़ते ग्लोबल असर और डिप्लोमैटिक पहुंच को दिखाता है।

यह अवॉर्ड बाइलेटरल रिश्तों में ऐतिहासिक पल के साथ भी मेल खाता है, क्योंकि यह देश की आज़ादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा है।

यह पहचान ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इनोवेशन, एजुकेशन और लोगों के बीच लेन-देन जैसे एरिया में इंडिया-स्लोवाकिया कोऑपरेशन की बढ़ती अहमियत को दिखाती है।

### भारत-स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करना

इस दौर के दौरान, भारत और स्लोवाकिया ने अपने रिश्ते को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक बढ़ाया और आपसी सहयोग में एक नया चैप्टर शुरू किया। खास सेक्टरों को कवर करने वाले 11 एग्रीमेंट्स और MoUs पर साइन किए हैं, जिनमें शामिल हैं,

- श्रमिक प्रवास
- रक्षा सहयोग
- डिजिटल प्रौद्योगिकियां
- उच्च शिक्षा और अनुसंधान
- नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदारी

इन एग्रीमेंट से सहयोग गहरा होने और इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट के नए मौके बनने की उम्मीद है।

### स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी का स्लोवाकिया दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि यह देश की आज़ादी के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑफिशियल दौरा है।

यह दौरा उनके बड़े यूरोपियन आउटरीच का हिस्सा है, जिसका मकसद ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूरोपियन पार्टनर्स के साथ सहयोग बढ़ाना है।

स्लोवाकिया का सबसे बड़ा नेशनल अवॉर्ड मिलना, दोनों देशों के बीच मज़बूत रिश्तों और भविष्य में सहयोग के लिए दोनों देशों के साझा कमिटमेंट को और दिखाता है।

### PM मोदी का फ्रांस दौरा: भारत, फ्रांस ने 13 मुख्य नतीजों का खुलासा किया और 2030 के लिए इनोवेशन रोडमैप अपनाया

भारत और फ्रांस ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान 13 खास नतीजों की घोषणा करके अपनी लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मज़बूत किया है। इन एग्रीमेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, ट्रेड, डिजिटल पेमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थकेयर, रेलवे, डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे कई सेक्टर शामिल होंगे।

### भारत-फ्रांस सामरिक संबंधों में नया अध्याय

नए नतीजे भारत-फ्रांस स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक अहम पड़ाव हैं। दोनों देशों ने ज़रूरी और नई टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इनोवेशन इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया है।

ये एग्रीमेंट दोनों देशों में बिज़नेस, रिसर्च, स्टार्टअप और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए नए मौके बनाते हुए, बाइलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने के बड़े मकसद से भी जुड़े हैं।

### 13 मुख्य नतीजों की लिस्ट

1. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और एजुकेशन में सहयोग को गाइड करने के लिए इंडिया-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाया
2. AI गवर्नेंस और ज़िम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने के लिए एक जॉइंट इंडिया-फ्रांस AI वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा।
3. NSTI, कानपुर में एरोनॉटिक्स और उससे जुड़े सेक्टर में स्किलिंग के लिए नेशनल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने के लिए MoU
4. डिजिटल पेमेंट सहयोग को मजबूत करने के लिए फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा।
5. फ्रांस के लीडिंग स्टार्टअप कैम्पस स्टेशन F में 10 और इंडियन स्टार्टअप्स का इनक्यूबेशन
6. भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और फ्रांस के INRIA के बीच डिजिटल विज्ञान केंद्र की स्थापना
7. अकादमिक सहयोग को गहरा करने के लिए यूनिवर्सिटी पेरिस-सैकले में "एआई, इनोवेशन और कल्चर" पर ICCR इंडिया चेयर की बैठक
8. डिजिटल हेल्थ रिसर्च में सहयोग के लिए ICMR और फ्रांस के हेल्थ डेटा हब के बीच लेटर ऑफ़ इंटेन्ट
9. अगले पांच सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने के लिए एक हाई-लेवल मैकेनिज्म बनाने पर सहमति
10. सप्लाय चेन और ज़रूरी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू करना
11. भारत में रेलवे और हाई-स्पीड रेल के विकास पर इरादे की घोषणा
12. दोनों देशों के बीच क्लासिफाइड जानकारी के एक्सचेंज और प्रोटेक्शन पर जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट
13. माइक्रोग्रैविटी रिसर्च और ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ISRO और फ्रांस के CNES के बीच लेटर ऑफ़ इंटेन्ट

### भारत-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 का अनावरण किया गया

सबसे ज़रूरी घोषणाओं में से एक इंडिया-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाया था।

यह रोडमैप सहयोग को गाइड करने के लिए लॉन्ग-टर्म फ्रेमवर्क का काम करेगा,

- प्रौद्योगिकी विकास
- अनुसंधान और नवाचार
- वैज्ञानिक सहयोग
- शिक्षा और कौशल विकास
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

इस पहल का मकसद इनोवेशन से होने वाली ग्रोथ को मज़बूत करना और दोनों देशों को नई टेक्नोलॉजी में लीडर बनाना भी है।

ये समझौते क्यों ज़रूरी हैं?

ये 13 नतीजे मिलकर दिखाते हैं कि भारत-फ्रांस के रिश्ते पारंपरिक डिप्लोमैटिक और डिफेंस रिश्तों से आगे बढ़ रहे हैं।

ये एग्रीमेंट फ्यूचर-ओरिएंटेड सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे,

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- डिजिटल नवाचार
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
- स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र
- आर्थिक सुरक्षा
- हरित और सतत विकास

वे मिलकर काम करने वाली लीडरशिप के साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आकार देने के लिए दोनों देशों के शेयर्ड विज़न को भी मज़बूत करते हैं।

### राष्ट्रीय समाचार

- FSSAI ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिए "हेल्दी," "ऑर्गेनिक," "ज़ीरो मैदा," "प्लांट-बेस्ड," और "वीगन" जैसे फूड पैकेजिंग दावों की मॉनिटरिंग तेज़ कर दी है। कंपनियों को यह पक्का करना होगा कि सभी दावे साइंटिफिक सबूतों से सपोर्टेड हों और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 और लेबलिंग नियमों का पालन करते हों। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर वैलिड सर्टिफिकेशन और जैविक भारत लोगो होना चाहिए। रेगुलेटर पेनल्टी लगा सकता है, लेबल में बदलाव का ऑर्डर दे सकता है, लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है, या प्रोडक्ट्स को वापस मंगा सकता है। इस पहल का मकसद भारत के बढ़ते हेल्थ-कॉन्शियस फूड मार्केट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ट्रांसपैरेंसी और भरोसा बढ़ाना है।
- आयुष मंत्रालय के ज़रिए एक नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (IDY) 2026 से पहले YouTube योग सेशन के लिए 435,831 वेरिफाइड लाइव दर्शकों को खींचकर बनाया गया। इस प्रोग्राम में कॉमन योग प्रोटोकॉल दिखाया गया और रोज़ाना योग करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए योग 365 कैम्पेन को बढ़ावा दिया गया। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ योग के सपोर्ट से आयोजित इस इवेंट में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और वेलनेस में योग की भूमिका पर ज़ोर दिया गया। यह उपलब्धि दुनिया भर में योग को बढ़ावा देने में भारत की लीडरशिप को दिखाती है और "स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग" थीम का समर्थन करती है।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) स्कीम ने जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने, चाइल्ड सेक्स रेश्यो में सुधार करने और लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ाने के 11 साल पूरे कर लिए हैं। 2015 में लॉन्च होने के बाद से, इंडिया का सेक्स रेश्यो जन्म के समय 918 से सुधारकर 929 हो गया, जबकि लड़कियों का सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट 75.51% से बढ़कर 80.2% हो गया। यह प्रोग्राम अवेयरनेस कैम्पेन, हेल्थकेयर सपोर्ट, न्यूट्रिशन और एजुकेशन इनिशिएटिव के ज़रिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करता है। कई मिनिस्ट्री के बीच कोऑर्डिनेशन से लागू किया गया, BBBP महिलाओं के नेतृत्व वाले डेवलपमेंट, इनक्लूसिव ग्रोथ और लड़कियों के एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने वाला एक देशव्यापी मूवमेंट बन गया है।
- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर अपनी पहली टनल हुड टेक्नोलॉजी लगाई है। ये खास तौर पर डिज़ाइन किए गए स्ट्रक्चर टनल के एंट्रेस और एग्जिट गेट पर लगाए गए हैं ताकि 300 kmph से ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेनों से पैदा होने वाले एयर-प्रेसर वेक्स को मैनेज किया जा सके। यह सिस्टम "टनल बूम" इफ़ेक्ट को कम करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन कम करता है, पैसेंजर कम्फर्ट को बेहतर बनाता है और ऑपरेशनल सेफ्टी को बढ़ाता है। जापान, फ्रांस और चीन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी से प्रेरित होकर, यह इनोवेशन हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने को दिखाता है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को मज़बूत करता है।
- इंदौर में 16वीं BRICS एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग में, मेंबर देशों ने एक जॉइंट डिक्लैरेशन अपनाया जिसमें फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर और छोटे किसानों को सपोर्ट देने पर ज़ोर दिया गया। खास पहलों में एग्रोइकोलॉजी पर सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस का BRICS नेटवर्क, एक डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क और सीड सिस्टम में किसानों के अधिकारों पर एक ग्लोबल फ़ोरम शामिल हैं। मीटिंग में BRICS AGRIN फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दी गई और एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफ़ॉर्म को नॉलेज-टू-एक्शन हब में बदल दिया गया। इन उपायों का मकसद BRICS देशों में एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और किसानों की भलाई को मज़बूत करना है।
- डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट्स ने हिमाचल प्रदेश में मंडी और रेहरधर के बीच ड्रोन-बेस्ड मेल ट्रांसमिशन सर्विस शुरू की है। पहले जो सफ़र दो घंटे से ज़्यादा का होता था, वह अब सिर्फ़ सात मिनट में पूरा हो सकता है। इस पहल से दूर और पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे मेल, पार्सल, फ़ाइनेंशियल सर्विस और सरकारी डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी तेज़ी से होगी। सफल ट्रायल के बाद, सरकार हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 रूट पर ड्रोन ऑपरेशन बढ़ाने की योजना बना रही है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल लॉजिस्टिक्स, सर्विस एफिशिएंसी और रीजनल इन्क्लूजन को बढ़ावा देता है।

- भारत के प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) ने तीन नए चूड़ों के साथ एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिससे कैद में रखे गए पक्षियों की संख्या 94 हो गई है। साइंटिफिक ब्रीडिंग तरीकों, जिसमें आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, नेचुरल ब्रीडिंग और जंपस्टार्ट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी शामिल हैं, ने प्रोग्राम की सफलता में योगदान दिया है। दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक, बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हैबिटाट के नुकसान और पावर-लाइन की टक्करों से खतरे का सामना कर रहा है। राजस्थान में कंज़र्वेशन की कोशिशों का मकसद जेनेटिक डायवर्सिटी में सुधार करना, जंगली आबादी को सपोर्ट करना और इस आइकॉनिक स्पीशीज़ के लंबे समय तक बने रहने को सुरक्षित करना है।
- इंदौर में हुई 16 वीं BRICS कृषि मंत्रियों की मीटिंग इंदौर डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ खत्म हुई, जिसमें फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, किसान कल्याण, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर और डिजिटल एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। छोटे और मार्जिनल किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास ज़ोर दिया गया। चार बड़ी पहलें शुरू की गईं, जिनमें BRICS नेटवर्क ऑफ़ सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस ऑन एग्रो-इकोलॉजी, BRICS डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क, ग्लोबल फ़ोरम ऑन फ़ार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टम्स और BRICS एग्रीएन फ़्रेमवर्क शामिल हैं। इस डिक्लेरेशन का मकसद BRICS देशों के बीच एग्रीकल्चरल इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी और ट्रेड को मज़बूत करना है।
- भारत सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए रावी और ब्यास जल ट्रिब्यूनल और कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल का समय एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद एक्ट, 1956 के तहत बनाए गए ये ट्रिब्यूनल आम नदी सिस्टम पर निर्भर राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दों को देखते हैं। यह कदम कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म, समान जल वितरण और संस्थागत विवाद समाधान के महत्व को दिखाता है। उनके फैसलों का खेती, उद्योग, पीने के पानी की सप्लाई और जल संसाधनों के टिकाऊ मैनेजमेंट पर काफी असर पड़ता है।
- इंडियन रेलवे ने क्वच 4.0 के डिप्लॉयमेंट में तेज़ी लाई है। यह इसका स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम है जिसे टक्कर, ओवरस्पीडिंग और सिग्नल पासिंग एट डेंजर (SPAD) घटनाओं को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस विस्तार में अहमदाबाद और अंबाला सहित प्रमुख रेलवे डिवीज़न के साथ-साथ दक्षिण भारत के मुख्य

कॉरिडोर भी शामिल हैं। एक नए LTE-बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के सपोर्ट से, क्वच रियल-टाइम ट्रेन मॉनिटरिंग और ऑटोमैटिक ब्रेकिंग को इनेबल करता है। इस पहल से रेलवे सेफ्टी में सुधार, इंसानी गलती से होने वाले एक्सीडेंट कम होने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने और भारत के रेलवे मॉडर्नाइज़ेशन प्रोग्राम को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।

- 2035 तक 155 GW विंड एनर्जी कैपेसिटी पाने का बड़ा टारगेट बताया है, और 2030 तक 100 GW का बीच का टारगेट रखा है। अभी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 56 GW से ज़्यादा है, जिससे भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, सरकार ने WT-MARUT पोर्टल लॉन्च किया, जिसका मकसद सप्लाई-चेन ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाना और घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। विंड एनर्जी भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन, एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स, ग्रीन जॉब क्रिएशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करते हुए कार्बन एमिशन कम करने के कमिटमेंट के लिए सेंट्रल बनी हुई है।
- 19 वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (MIFF) 2026 मुंबई में शुरू हुआ, जिसने नॉन-फीचर सिनेमा को डेडिकेटेड एशिया के लीडिंग फेस्टिवल के तौर पर अपनी जगह पक्की की। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NFDC) द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए इस फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्मों, एनिमेशन और डिजिटल स्टोरीटेलिंग दिखाई जाती है। इस साल की एक बड़ी खासियत AI-जेनरेटेड फिल्मों का शामिल होना है, जो फिल्ममेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते असर को दिखाता है। MIFF 2026 क्रिएटिविटी, कल्चरल एक्सचेंज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और उभरते स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है।

**Test Prime**

ALL EXAMS  
ONE SUBSCRIPTION

- **मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ( MeitY )** ने **NEET UG 2026** री-एग्जामिनेशन से पहले **22 जून 2026** तक **टेलीग्राम** के एक्सेस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह फैसला **नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)** की सिफारिशों के बाद लिया गया ताकि नकली क्वेश्चन पेपर, आंसर की और गुमराह करने वाले कंटेंट के सर्कुलेशन को रोका जा सके। अधिकारियों ने टेलीग्राम को अपने मैसेज-एडिटिंग फीचर को कुछ समय के लिए बंद करने का भी निर्देश दिया है। इस कदम का मकसद एग्जाम की ईमानदारी बनाए रखना, कथित गड़बड़ी की जांच में मदद करना और एक निष्पक्ष और पारदर्शी एग्जाम प्रोसेस पक्का करना है।
- **आयुष मंत्रालय** ने **योग पार्क पोर्टल** लॉन्च किया है, जो एक देशव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद पब्लिक पार्कों को कम्युनिटी वेलनेस सेंटर में बदलना है। **इंटरनेशनल योग दिवस 2026** के काउंटडाउन के दौरान शुरू की गई यह पहल लोकल बॉडीज़, **NGOs**, **रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs)** और कॉर्पोरेट संस्थाओं को योग, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ के लिए खास जगहें बनाने के लिए बढ़ावा देती है। यह पोर्टल वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लागू करने की गाइडलाइंस, रजिस्ट्रेशन में मदद और रिसोर्स देता है। यह पहल शहरी और ग्रामीण भारत में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, पब्लिक पार्टिसिपेशन और रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल करने को बढ़ावा देती है।
- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** ने **ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026** के तहत कफ सिरप समेत सिरप वाली दवाएं खरीदने के लिए **डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन** ज़रूरी कर दिया है। **बेनाड्रिल**, **ग्लाइकोडिन** और **ग्रिलिंक्टस** जैसे पाँपुलर प्रोडक्ट्स के लिए अब मेडिकल ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत होगी। यह कदम **ड्रग्स रूल्स, 1945** के **शेड्यूल K** से सिरप फॉर्मूलेशन को हटाने के बाद उठाया गया है। इस रेगुलेशन का मकसद **ड्रग सेफ्टी को बेहतर बनाना**, गलत इस्तेमाल को रोकना, लिक्विड दवाओं की मॉनिटरिंग को मज़बूत करना और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए सही मेडिकल सुपरविज़न पक्का करना है।
- **किशाऊ मल्टी-पर्पस डैम प्रोजेक्ट** में एक बड़ी सफलता मिली है, जब छह राज्य - **हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान** - एक मेमोरेण्डम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए। इस प्रोजेक्ट का मकसद **वाटर सिक्योरिटी में सुधार करना, यमुना बेसिन** की इकोलॉजिकल हेल्थ को बेहतर बनाना, पीने के पानी की सप्लाई में मदद करना और **हाइड्रोपावर बनाना** है। केंद्र पानी के हिस्से की लागत का **90% फंड देगा**। इस पहल से उत्तर भारत में **इंटर-स्टेट कोऑपरेशन**, नदी के जीर्णोद्धार और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को मज़बूती मिलने की उम्मीद है।
- भारत सरकार ने **डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय** को चेयरपर्सन और **प्रो. शुभब्रत दास**, **सत्येंद्र बहादुर सिंह** और **माधवन मुकुंद** को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन (NSC) का मेंबर बनाया है। 2005 में बनी NSC, भारत की सबसे बड़ी स्टैटिस्टिकल एडवाइज़री बॉडी है, जो डेटा क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार है। नई नियुक्तियों से **डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस को मज़बूत करने**, स्टैटिस्टिकल एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने और पॉलिसी बनाने और डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए भारत के ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और असर में सुधार होने की उम्मीद है।
- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 15 जून 2026 को **कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA)** और **डबल कंट्रीव्यूशन कन्वेंशन** को लागू किया। इन एग्रीमेंट का मकसद **बाइलेटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल मोबिलिटी को बढ़ावा देना** है। CETA के तहत, **इंडियन एक्सपोर्टर्स** को लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर **ज़ीरो-ड्यूटी एक्सेस** मिलता है, जबकि सोशल सिक्योरिटी पैकट इंडियन प्रोफेशनल्स को पांच साल तक के ओवरसीज असाइनमेंट के दौरान **डुअल कंट्रीव्यूशन** से छूट देता है। इन एग्रीमेंट से इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ने और बिजनेस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए मौके बनने की उम्मीद है।
- भारत सरकार ने **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** के तहत नौ **स्टार्टअप्स** के लिए **₹ 22 करोड़** की फाइनेंशियल मदद को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री **प्रल्हाद जोशी** ने बताया कि यह फंडिंग **हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन** और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को सपोर्ट करती है। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी और कम्प्लायंस पक्का करने के लिए **भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल** भी लॉन्च किया है। यह पहल **2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन** बनाने के भारत के टारगेट में मदद करती है, जिससे देश के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन और सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को मज़बूती मिलती है।
- ऐतिहासिक **कादियान-ब्यास रेलवे लाइन प्रोजेक्ट** को लगभग एक सदी बाद फिर से शुरू किया गया है। **39.68 km का ब्रॉड-गेज कॉरिडोर** कादियान और ब्यास को घुमान, **बुटाला और सधियाला** जैसे खास शहरों से जोड़ेगा। **कवच सेफ्टी टेक्नोलॉजी**, एडवांस्ड सिग्नलिंग सिस्टम, बड़े पुल और रोड अंडरपास से लैस यह प्रोजेक्ट इलाके की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और **अमृतसर-पठानकोट सेक्शन** के लिए एक दूसरा रास्ता देगा। इससे धार्मिक जगहों तक पहुंच बढ़ेगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, **इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मज़बूत होगा** और पंजाब के माझा इलाके में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में "वन नेशन, वन एक्सपो" थीम के तहत हुआ। इस इवेंट में 90 से ज्यादा देशों के पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया और कंस्ट्रक्शन मटीरियल, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, सीमेंट, सिरिमेक्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स समेत 24 सेक्टर्स में इनोवेशन दिखाए गए। इस एग्जिबिशन का मकसद टेक्नोलॉजी अपनाने, इंटरनेशनल ट्रेड, इनोवेशन और मैनुफैक्चरिंग में बेहतरीन काम को बढ़ावा देना है। लीडर्स ने एक्सपोर्ट के मौके बनाने और ग्लोबल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर हब के तौर पर भारत की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में इंडिया-UK CETA जैसे ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स की भूमिका पर जोर दिया।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें घोषणा की गई कि सुरक्षित और सीमांकित फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। यह फैसला न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंद्रकर की पीठ ने एक मोटर दुर्घटना मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया। इस मामले में पांच साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसे एक टैंकर ने उस सड़क पर टक्कर मार दी थी जहां फुटपाथ और पैदल यात्री क्रॉसिंग नहीं थी। न्यायालय ने मुआवजा बहाल किया और बढ़ाकर ₹ 11.44 लाख कर दिया, इस बात पर जोर दिया कि पैदल चलने वालों के अधिकार शहरी नियोजन का अभिन्न अंग होने चाहिए और शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों, पंचायतों और स्थानीय सरकारों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने का निर्देश दिया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुडा जिले के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक पैमाने की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखी। 25,016 करोड़ रुपये की यह परियोजना भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) द्वारा विकसित की जाएगी, जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का एक संयुक्त उद्यम है। स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए, संयंत्र कोयले को सिनगैस में परिवर्तित करेगा और प्रति दिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगा। 350 एकड़ में फैले इस परियोजना को कोयला मंत्रालय की प्रोत्साहन योजना के तहत 1,350 करोड़ रुपये मिले हैं। इसका उद्देश्य आयातित रसायनों पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, घरेलू कोयला भंडार से मूल्यवर्धन को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और सरकार के आत्मनिर्भर भारत और कोयला गैसीकरण लक्ष्यों का समर्थन करना है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने NH -48 के दिल्ली-जयपुर खंड पर दौलतपुरा टोल प्लाजा पर राजस्थान का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम शुरू किया है। बाधा रहित टोलिंग प्रणाली, FASTag- आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) तकनीक को जोड़ती है, जिससे वाहनों को बिना रुके गुजरने की अनुमति मिलती है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे पंजीकरण संख्याओं को कैप्चर करते हैं और लिंक किए गए FASTag खातों से स्वचालित रूप से टोल शुल्क काट लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना, यात्रा का समय कम करना, ईंधन दक्षता में सुधार करना, वाहनों से उत्सर्जन को कम करना और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है। इसके सफल रोलआउट के बाद, NHAI की योजना शाहजहांपुर और मनोहरपुर टोल प्लाजा पर MLFF तकनीक का विस्तार करने की है,
- भारत मंगलुरु में एक नए रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) सुविधा के विकास के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तैयार है। इस परियोजना को तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को सौंपा गया है, जो ₹ 15,000 करोड़ की अनुमानित लागत से 1.75 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की क्षमता वाली एक भूमिगत कच्चे तेल भंडारण गुफा का निर्माण करेगा। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भू-राजनीतिक संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं या बाजार में अस्थिरता के कारण आपूर्ति व्यवधानों का प्रबंधन करने के लिए आपातकालीन भंडार के रूप में कार्य करते हैं। भारत वर्तमान में विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में 5.33 एमएमटी की संयुक्त क्षमता के साथ एसपीआर सुविधाएं संचालित करता है। नई सुविधा से भंडारण क्षमता में लगभग एक तिहाई की वृद्धि होगी। कुल परियोजना लागत में से लगभग ₹ 5,000 करोड़ बुनियादी ढांचे पर और ₹ 10,000 करोड़ कच्चे तेल की खरीद और भंडारण पर खर्च किए जाएंगे।

### राज्य समाचार

- मछली पालन सेक्टर को मजबूत करने के लिए भोजपुर में ₹ 31.21 करोड़ का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाएगा। इस सुविधा में हैचरी, फ्रीड प्लांट, डायग्नोस्टिक लैब, बायोफ्लोक यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर शामिल होंगे। इसके साथ ही, पटना में NFDB रीजनल सेंटर मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा। ₹ 902.84 करोड़ के मछली पालन प्रोजेक्ट्स की मदद से, बिहार भारत का चौथा सबसे बड़ा इनलैंड मछली उत्पादक राज्य बन गया है। इस पहल का मकसद मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजी-रोटी में सुधार करना, सस्टेनेबल मछली पालन मैनेजमेंट को बढ़ावा देना और ग्रामीण आर्थिक विकास में मदद करना है।

- झारखंड के भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बैम्बू क्राफ्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिले हैं। यह पहचान इन प्रोडक्ट्स की असली पहचान को बचाती है और उनके कल्चरल और रीजनल महत्व को दिखाती है। GI स्टेटस नकल रोकने, मार्केट वैल्यू सुधारने, एक्सपोर्ट बढ़ाने और कारीगरों के लिए बेहतर इनकम के मौके बनाने में मदद करता है। यह डेवलपमेंट झारखंड की पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट और सेरीकल्चर विरासत को मजबूत करता है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देता है और देसी ज्ञान सिस्टम को बचाता है।
- केरल ने प्रियदर्शिनी फ्री बस ट्रेवल स्कीम शुरू की है, जिससे महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को KSRTC की आम बसों में ज़ीरो-फ़ेयर यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह स्कीम सबके लिए है, इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन या इनकम क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, और अभी इसमें लगभग 3,125 बसें शामिल हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करके, इस पहल का मकसद शिक्षा, रोज़गार, हेल्थकेयर और पब्लिक सर्विस तक पहुँच को बेहतर बनाना है। इससे वर्कफ़ोर्स में भागीदारी, सोशल इन्क्लूजन और जेंडर एम्पावरमेंट बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही केरल के बड़े वेलफेयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकसद को भी सपोर्ट मिलेगा।
- केरल ने विज़न 2031 पेश किया है, जो भारत का सबसे ज़्यादा महिला-फ्रेंडली राज्य बनने का एक बड़ा रोडमैप है। यह स्ट्रैटेजी महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, मोबिलिटी, कानूनी सुधार और जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर फोकस करती है। प्रस्तावित उपायों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक ट्रायल, महिला पुलिस थानों का विस्तार, एक डिस्ट्रेस अलर्ट ऐप, पिक बसें और अवलकोपम जैसे सपोर्ट प्रोग्राम शामिल हैं। ₹ 5,586.99 करोड़ के जेंडर बजट एलोकेशन के साथ, इस पहल का मकसद महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक सुरक्षित, ज़्यादा समावेशी और आर्थिक रूप से मजबूत माहौल बनाना है।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजा परबा के महत्व पर ज़ोर दिया। यह ओडिशा का पारंपरिक त्योहार है जो प्रकृति, खेती और मानसून के आने का जश्न मनाता है। यह त्योहार भगवान शिव का सम्मान करता है। कल्चरल इवेंट्स, झूलों, लोक गीतों और पोड़ा पीठा और मंडा पीठा जैसे पारंपरिक खाने के ज़रिए धरती माँ, उपजाऊपन और इकोलॉजिकल बैलेंस को बढ़ावा दिया जाता है। राजा परबा ओडिशा की खेती की विरासत को दिखाता है और इंसानों और प्रकृति के बीच तालमेल को बढ़ावा देता है। यह त्योहार पर्यावरण के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक बचाव और कम्युनिटी बॉन्डिंग को भी मजबूत करता है।
- असम ने कार्बी आंगलोग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, असम बिहू पेपा, असम बैम्बू क्राफ्ट्स और देउरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग हासिल किए हैं। NABARD के सपोर्ट से, यह पहचान पारंपरिक ज्ञान और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करती है और कारीगरों के लिए मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाती है। GI सर्टिफिकेशन कल्चरल प्रोटेक्शन को मजबूत करता है, ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए आर्थिक मौके बढ़ाता है। इन चीज़ों के साथ, असम में अब 12 NABARD-सपोर्टेड GI-सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जो राज्य की रिच विरासत और कारीगरी को दिखाते हैं।
- महाराष्ट्र कैबिनेट ने नागपुर में ₹ 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ हार्ड-एनर्जी मेडिकल साइक्लोड्रॉन प्रोजेक्ट (HEMCP) को मंजूरी दे दी है। यह फैसिलिटी PET-CT स्कैन, न्यूक्लियर मेडिसिन और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेडियोआइसोटोप बनाने के लिए एक रेडियोफार्मास्युटिकल इन्वेस्टमेंट हब बनाएगी। यह प्रोजेक्ट बाहरी सप्लायर पर निर्भरता कम करेगा और पूरे सेंट्रल इंडिया में हेल्थकेयर एक्सेस को बेहतर बनाएगा। इसके साथ ही, राज्य ने महाराष्ट्र रूरल ड्रिंकिंग वॉटर पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी, जो सस्टेनेबल वॉटर मैनेजमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग और बेहतर रूरल वॉटर सप्लाई सिस्टम पर फोकस करती है।
- पारंपरिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट त्रिपुरा सरिंडा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिला है, जिससे त्रिपुरा के लोकल समुदायों के बीच इसके खास कल्चरल महत्व को पहचान मिली है। लकड़ी के एक ही ब्लॉक से हाथ से बनाया गया और धनुष से बजाया जाने वाला सरिंडा लोक संगीत, समारोहों और बोलचाल की परंपराओं का एक अहम हिस्सा है। यह पहचान इंस्ट्रूमेंट को नकल से बचाती है, लोकल कारीगरों को सपोर्ट करती है और कल्चरल विरासत को बचाने को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही, त्रिपुरा के पास अब चार GI-टैग वाले प्रोडक्ट हैं, जो इसकी शानदार कलात्मक और कल्चरल परंपराओं को दिखाते हैं।
- क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र (आरएचआरएस), लाम फार्म, गुंटूर ने लोकप्रिय तेजा और ब्यादगी का विकल्प प्रदान करने के लिए दो नई मिर्च किस्में- एलसीए-625 और एलसीए-643 पेश की हैं। मिर्च। LCA-625 एक तेज़ तीखेपन वाली सूखी मिर्च की किस्म है, जबकि LCA-643 हरी और सूखी दोनों तरह की मिर्च की खेती के लिए सही है और इसमें कीड़ों और बीमारियों के लिए ठीक-ठाक प्रतिरोधक क्षमता है। इस डेवलपमेंट का मकसद प्रोडक्टिविटी में सुधार करना, मसाला प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना और किसानों की इनकम बढ़ाना है। इस रिलीज़ से आंध्र प्रदेश की मिर्च उगाने वाले बड़े राज्य के तौर पर स्थिति और मजबूत होती है।

- ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल क्लीयरेंस अथॉरिटी के ज़रिए 20 प्रस्तावों में ₹ 76,611.86 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। ये प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थकेयर, स्टील, रेलवे, ज़रूरी मिनरल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में फैले हुए हैं। 50,500 से ज्यादा जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है, इन इन्वेस्टमेंट्स में बड़ी कंपनियों के प्रस्ताव शामिल हैं और यह लैब-ग्रोन डायमंड मैनुफैक्चरिंग और एडवांस्ड मटीरियल्स में ओडिशा की एंट्री को दिखाता है। यह पहल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन, रोजगार पैदा करने और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है।
- मध्य प्रदेश सरकार जुलाई 2026 में राज्य विधानसभा के मानसून सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल लाने का प्लान बना रही है। प्रस्तावित कानून शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार को कंट्रोल करने वाले कॉमन सिविल नियम बनाने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रसाद देसाई की अगुवाई वाली एक कमेटी ने काफ़ी सलाह-मशविरे के बाद ड्राफ्ट तैयार किया। यह कदम संविधान के आर्टिकल 44 के मुताबिक है और इसका मकसद कानूनी एकरूपता को बढ़ावा देना है, साथ ही ज़रूरी पब्लिक और पॉलिटिकल बहस भी पैदा करना है।
- मिशमी ताकिन ( बुडोरकास) के झुंड का पहला वीडियो साक्ष्य रिकॉर्ड किया (टैक्सीकलर ) नॉर्थ सिक्किम के टिंगडा रिज़र्व फ़ॉरेस्ट में। आठ लोगों के एक ग्रुप को डॉक्यूमेंट किया गया, जो इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया सीन है। IUCN द्वारा वल्नरेबल के तौर पर क्लासिफ़ाई किया गया, मिशमी ताकिन अल्पाइन इकोसिस्टम हेल्थ का एक ज़रूरी इंडिकेटर है। यह खोज पूर्वी हिमालय की रिच बायोडायवर्सिटी को हाईलाइट करती है और रेयर माउंटेन स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए हैबिटाट कंज़र्वेशन और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करती है।
- ओडिशा सरकार ने ₹ 76,611.86 करोड़ के 20 इन्वेस्टमेंट प्रोज़ेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिससे नौ ज़िलों में 50,500 से ज्यादा नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थकेयर, रेलवे, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी मिनरल जैसे सेक्टर में हैं। इसमें टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, L&T, रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और श्याम मेटालिक्स जैसी बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं। इन मंजूरीयों से ओडिशा लैब में बने डायमंड मैनुफैक्चरिंग और एडवांस्ड मटीरियल प्रोडक्शन से भी जुड़ गया है। यह पहल इंडस्ट्रियल डायवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल

डेवलपमेंट, रोजगार पैदा करने में मदद करती है और ओडिशा की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थिति को मज़बूत करती है।

- ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार, AI-नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में बेंगलुरु, बीजिंग के बाद एशिया में दूसरे स्थान पर है। इस शहर में 606 AI स्टार्टअप, लगभग 600,000 AI प्रोफेशनल और 30 यूनिफ़ॉर्म हैं, जो इसे दुनिया के सबसे डायनामिक इनोवेशन इकोसिस्टम में से एक बनाता है। बेंगलुरु ने 2021 और 2025 के बीच वेंचर कैपिटल फंडिंग में \$39 बिलियन आकर्षित किए और स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया भर में 15वें स्थान पर रहा। यह पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी से चलने वाली आर्थिक ग्रोथ में भारत की लीडरशिप को और मज़बूत करती है।
- सब्जी मंडी इलाके में अपना पहला ऑल-वुमन पुलिस स्टेशन खोला। पूरी तरह से महिला कर्मचारियों वाला यह स्टेशन महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, पीछा करना, परेशान करना और मारपीट जैसे अपराधों पर फोकस करता है। लॉ एनफोर्समेंट के अलावा, यह काउंसलिंग सेशन, कानूनी जागरूकता कैंपेन और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम भी चलाएगा। इस पहल का मकसद ज्यादा जेंडर-सेंसिटिव पुलिसिंग सिस्टम बनाना, मदद मांगने वाली महिलाओं के लिए पहुंच को बेहतर बनाना और महिलाओं की सुरक्षा और एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हुए लॉ एनफोर्समेंट में लोगों का भरोसा मज़बूत करना है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की उपस्थिति में मेघालय में ₹ 1,246 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाओं में सड़क संपर्क, रसद, पर्यटन बुनियादी ढांचा, शिक्षा और आजीविका विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। एक प्रमुख घटक मेघालय लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य परिवहन नेटवर्क को मज़बूत करना, रसद लागत को कम करना, ग्रामीण संपर्क में सुधार करना और खेत से बाजार तक संपर्क बढ़ाना है। अतिरिक्त निवेश से दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार होगा, व्यापार को सुविधाजनक बनाया जाएगा, पर्यटन को समर्थन दिया जाएगा और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन केंद्रित पहल पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय उद्यमों के लिए अवसर पैदा करेगी, जबकि शिक्षा और आजीविका कार्यक्रमों में निवेश मानव पूंजी को मज़बूत करेगा, उद्यमशीलता का समर्थन करेगा और पूरे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

- तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत पाँच डेडिकेटेड रिन्यूएबल एनर्जी ज़ोन बनाने को मंजूरी दी है। इन ज़ोन के हेडक्वार्टर चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, कोयंबटूर और मदुरै में होंगे और ये तय बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल के अंदर प्रोजेक्ट्स की देखरेख करेंगे। इस पहल का मकसद मंजूरीयों को आसान बनाना, स्टेकहोल्डर्स के बीच तालमेल बेहतर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना और पावर ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन में मदद करना है। हर ज़ोन को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लीड करेंगे जो प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पावर इन्फ्रैक्चर सिस्टम और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार होंगे। ये ज़ोन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे क्लीन एनर्जी में तमिलनाडु की लीडरशिप मज़बूत होगी और भारत के बड़े क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को सपोर्ट मिलेगा।
- भारत सरकार ने MHA, लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (22 मई, 2026) के साथ बातचीत में आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा की है। फोकस एक कस्टमाइज़्ड गवर्नेंस मॉडल पर है जो लोकल भागीदारी, सांस्कृतिक सुरक्षा, ज़मीन के अधिकार और एडमिनिस्ट्रेटिव जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ऑप्शन में सीमित शक्तियों वाली एक चुनी हुई UT-लेवल की बॉडी शामिल है, जबकि छठी अनुसूची की मांग पर विचार किया जा रहा है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरे राज्यों में आर्टिकल 371 के प्रावधान इन चर्चाओं को गाइड करते हैं ताकि क्षेत्रीय स्वायत्तता को राष्ट्रीय हितों के साथ बैलेंस किया जा सके।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत और फ्रांस ने 13 बड़े नतीजों की घोषणा की, जिससे उनकी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मज़बूत हुई। खास पहलों में इंडिया-फ्रांस इनोवेशन रोडमैप 2030, एक जॉइंट AI वर्किंग ग्रुप, बड़ी हुई UPI सर्विस, स्टार्टअप कोलेबोरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, रेलवे प्रोजेक्ट और ISRO और CNES के बीच स्पेस रिसर्च पार्टनरशिप शामिल हैं। दोनों देश पांच साल के अंदर आपसी व्यापार को दोगुना करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए, जिससे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्थिक सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनका कमिटमेंट दिखा।
- इंडिया-फ्रांस ATL ब्रिज को दोनों देशों के युवा इनोवेटर्स, स्कूलों और एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन और ला फाउंडेशन डिसॉल्ट सिस्टम्स के बीच सहयोग से डेवलप की गई यह पहल स्टूडेंट एक्सचेंज, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगी। फ्रांस भारत के अटल टिकरिंग लैब मॉडल पर आधारित अपनी पहली स्कूल इनोवेशन लैब भी बनाएगा। यह प्रोग्राम एजुकेशनल सहयोग को मजबूत करता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है और भारत और फ्रांस के बीच लोगों के बीच संबंधों को गहरा करता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया दौरा 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला सरकारी दौरा था। बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, इनोवेशन, ऑटोमोबाइल, रेलवे और लेबर मोबिलिटी में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहा। दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि डिफेंस में सहयोग और लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। यह दौरा बढ़ते स्ट्रेटेजिक जुड़ाव को दिखाता है और स्लोवाकिया को सेंट्रल यूरोप में भारत के लिए एक ज़रूरी पार्टनर के तौर पर दिखाता है।
- फ्रांस में 52 वें G7 समिट में बड़ी एडवांसड इकॉनमी के लीडर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, ज़रूरी मिनरल्स, सप्लाय चेंस और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। US-ईरान के बीच संभावित समझौते और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की खबरों के बीच इस समिट को अहमियत मिली, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट स्थिर हो सकते हैं। भारत ने एक पार्टनर देश के तौर पर हिस्सा लिया, जिससे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ग्लोबल गवर्नेंस चर्चाओं में इसकी बढ़ती भूमिका पर ज़ोर दिया गया।

### अंतरराष्ट्रीय समाचार

- अमेरिका और ईरान के बीच एक अस्थायी समझ है, जिसे पाकिस्तान, कतर, तुर्की और सऊदी अरब की रीजनल डिप्लोमेसी का सपोर्ट मिला है। प्रस्तावित उपायों में समुद्री पाबंदियों में ढील देना, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना और एक बड़े रीजनल सीज़फ़ायर फ्रेमवर्क को सपोर्ट करना शामिल है। इस डेवलपमेंट से एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर हो सकती है, तेल मार्केट स्थिर हो सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट कम हो सकती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो सकते हैं। भारत के लिए, आसान एनर्जी सप्लाय और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होने से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेड पर अच्छा असर पड़ सकता है।

- भारत इनोवेट्स 2026 समिट में भारत के बढ़ते डीप-टेक इकोसिस्टम को दिखाया गया, जिसमें 120 से ज़्यादा स्टार्टअप, 20 इंस्टीट्यूट और 350 ग्लोबल इन्वेस्टर शामिल थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और क्लीन एनर्जी में इनोवेशन पेश किए गए। इस इवेंट ने इनोवेशन में भारत-फ्रांस के सहयोग को मज़बूत किया और रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के ज़रिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब बनने के भारत के सपने को दिखाया।
- मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ़ ईरान के सबसे असरदार पॉलिटिकल लोगों में से एक हैं, जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और देश की पॉलिसी बनाने और स्ट्रेटिजिक मामलों में अहम भूमिका निभाते हैं। IRGC के पूर्व कमांडर, पुलिस चीफ़ और तेहरान के मेयर के तौर पर, उन्हें गवर्नेंस और सिक्योरिटी में दशकों का अनुभव है। उनका असर घरेलू पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी की चर्चाओं तक फैला हुआ है, जिससे वे ईरान की भविष्य की पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक दिशा को बनाने में एक अहम व्यक्ति बन गए हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। दोनों देशों ने रिश्तों को एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक बढ़ाया और डिफेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, रिसर्च, एजुकेशन, टूरिज्म और लेबर मोबिलिटी को कवर करने वाले 11 एग्रीमेंट पर साइन किए। नई पहलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्युनिकेशन और काउंटर-टैरिज्म में सहयोग शामिल है, जो एक गहरी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप और बढ़ते आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल सहयोग को दिखाता है।
- पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 के तहत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM) के लिए इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क अपनाया है। यह मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए लो-कार्बन प्रोजेक्ट्स पर सहयोग को मुमकिन बनाता है, जिसके नतीजे में कार्बन क्रेडिट दोनों देशों के बीच शेयर किए जाते हैं। यह फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट अप्रूवल, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन और क्रेडिट जारी करने के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाता है, साथ ही एमिशन में कमी की डबल काउंटिंग को रोकता है। यह पहल दोनों देशों को उनके नेशनली डिटरमाइंड कंटीरिब्यूशन (NDCs) को पाने और क्लाइमेट गोल्स को आगे बढ़ाने में मदद करती है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी ने जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOIA) के लिए बातचीत शुरू करने और 2026 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) को पूरा करने की कोशिशों में तेज़ी लाने पर सहमति जताई। प्रस्तावित एग्रीमेंट से डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, ज़रूरी मिनरल्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में सहयोग मज़बूत होगा। यह डेवलपमेंट भारत और कनाडा के बीच बढ़ते स्ट्रेटिजिक जुड़ाव और इकोनॉमिक सहयोग को दिखाता है।
- G7 समिट 2026 में, भारत इबोला के दोबारा फैलने से निपटने और कैंसर के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन को मज़बूत करने के लिए ग्लोबल कोशिशों में शामिल हुआ। पार्टनर देशों के साथ, भारत ने वैक्सीन डेवलपमेंट, बीमारी की निगरानी, डायग्नोस्टिक रिसर्च और पब्लिक हेल्थ की तैयारी से जुड़ी कोशिशों का सपोर्ट किया। समिट में सस्ती हेल्थकेयर एक्सेस, कैंसर का जल्दी पता लगाने और इंटरनेशनल रिसर्च में सहयोग पर भी ज़ोर दिया गया। भारत का हिस्सा लेना ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी में उसकी बढ़ती भूमिका और दुनिया भर में हेल्थ चुनौतियों से निपटने में मल्टीलेटरल सहयोग को दिखाता है।
- गैलरीज़ लाफ़ायेट नाइस मैसेना में सर्विस लॉन्च करके यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) की इंटरनेशनल पहुंच को बढ़ाया है। इस पहल को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और लायरा कलेक्ट ने आसान बनाया, जिससे भारतीय विज़िटर्स फ्रांस में बिना किसी रुकावट के QR-वेल्ड पेमेंट कर सकते हैं। UPI अब नौ देशों में चल रहा है, जिनमें फ्रांस, सिंगापुर, UAE, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया शामिल हैं। इस बढ़ोतरी से डिजिटल पेमेंट में भारत की लीडरशिप मज़बूत होगी और क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।



- यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर वापस यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड कर दिया है। असल में 1947 में बनी इस कमांड का नाम 2018 में इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटिजिक कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए बदला गया था। हालांकि पुराना नाम वापस ले लिया गया है, लेकिन इसके मिशन, लोगों और ऑपरेशनल जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह कमांड US के वेस्ट कोस्ट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैले दुनिया के सबसे स्ट्रेटिजिक रूप से ज़रूरी इलाकों में से एक की देखरेख करती है।
- अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग की घोषणा की, जो एक 14-पाइंट का अंतरिम फ्रेमवर्क है जिसका मकसद इलाके के तनाव को कम करना और बड़े पैमाने पर डिप्लोमैटिक बातचीत को आसान बनाना है। इस समझौते में मिलिट्री तनाव को रोकने, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और बैन हटाने और इलाके की स्थिरता पर बातचीत करने के वादे शामिल हैं। इस डेवलपमेंट से ग्लोबल एनर्जी मार्केट को सपोर्ट मिलने, समुद्री सुरक्षा में सुधार होने और दोनों देशों के बीच लगातार डिप्लोमैटिक बातचीत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- फ्रांस में गैलरीज लाफायेट नाइस मैसेना में लॉन्च के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की इंटरनेशनल पहुंच को बढ़ाया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और लायरा कलेक्ट के बीच सहयोग से लागू किया गया यह इंटीग्रेशन भारतीय विज़िटर्स को विदेश में तुरंत QR-कोड-बेस्ड डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देता है। UPI अब नौ देशों में चालू है, जिससे यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ी है और भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को दुनिया भर में स्वीकार करने में मदद मिली है। यह विस्तार भारत-फ्रांस डिजिटल सहयोग को भी मजबूत करता है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन में भारत की लीडरशिप को दिखाता है।
- यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड का नाम फिर से शुरू कर दिया है, 2018 में हुए बदलाव को पलटते हुए इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया गया था। नाम तो बदल गया है, लेकिन कमांड का मिशन, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, लोग और ज्योग्राफिकल जिम्मेदारियां वैसी ही रहेंगी। 1947 में बनी यह सबसे पुरानी और सबसे बड़ी US कॉम्बैटेंट कमांड है। इस कदम को काफी हद तक सिंबॉलिक और एडमिनिस्ट्रेटिव माना जा रहा है, जो ऐतिहासिक नाम पर वापसी दिखाता है, जबकि एशिया-पैसिफिक रीजन में वही स्ट्रेटिजिक फोकस बनाए रखता है, जिसमें इंडिया की वेस्टर्न बाउंड्री तक के एरिया भी शामिल हैं।
- अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए, जो इलाके के तनाव को कम करने के लिए बनाया गया 14-पाइंट का अंतरिम समझौता है। इस समझौते में 60-दिन का बातचीत का फ्रेमवर्क, मिलिट्री तनाव से बचने के वादे, और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की योजना बनाई गई है, जो एक ज़रूरी ग्लोबल एनर्जी रूट है। इसमें पाबंदियों में राहत और ईरानी तेल एक्सपोर्ट पर भी चर्चा शामिल है, जबकि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने का अपना वादा दोहराया है। इस समझौते से इलाके की स्थिरता, डिप्लोमैटिक जुड़ाव और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भरोसे में सुधार होने की उम्मीद है।
- पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत को एक भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के तौर पर तेज़ी से पहचाना जा रहा है। उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इनक्लूसिव ग्रोथ में भारत की तरक्की पर ज़ोर दिया, साथ ही इंटरनेशनल रिश्तों में भरोसे की अहमियत पर भी ज़ोर दिया। G7 समिट 2026 में हुई चर्चाओं का जिक्र करते हुए, उन्होंने इनक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस, जिम्मेदार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और विकासशील देशों के लिए मज़बूत रिप्रेजेंटेशन की वकालत की। उन्होंने डिफेंस, स्पेस, क्लाइमेट एक्शन, ट्रेड और साइबरनेटिक रिसर्च में भारत-फ्रांस के बढ़ते सहयोग पर भी ज़ोर दिया।
- उज़्बेकिस्तान, BRICS देशों द्वारा बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में शामिल होने वाला पहला सेंट्रल एशियाई देश बन गया है। शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उज़्बेकिस्तान बैंक का 10वां सदस्य बन गया, जिससे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लंबे समय की फाइनेंसिंग मिल गई। 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, NDB ने लगभग US\$43 बिलियन के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यह सदस्यता उज़्बेकिस्तान के मॉडर्नाइज़ेशन लक्ष्यों का समर्थन करती है और क्षेत्रीय और ग्लोबल आर्थिक सहयोग में इसकी बढ़ती भूमिका को दिखाती है।
- फ्रांस अपने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाला है, जो पूरी तरह से भारत से लाए गए पत्थरों से बना है और भारतीय कारीगरों ने इसे बनाया है। यह मंदिर असली हिंदू आर्किटेक्चरल सिद्धांतों को फॉलो करता है और इसका उद्घाटन 15 दिन के कल्चरल और धार्मिक उत्सव के साथ होगा। उम्मीद है कि यह विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल और कल्चरल हब के तौर पर काम करेगा, साथ ही कल्चरल लेन-देन को बढ़ावा देगा और विदेशों में भारतीय परंपराओं को बचाए रखेगा। यह प्रोजेक्ट बढ़ते भारत-फ्रांस कल्चरल रिश्तों की निशानी है और भारतीय विरासत की ग्लोबल मौजूदगी को दिखाता है।

- यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा नियम बनाया है, जिसमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की कम से कम उम्र 15 साल तय की गई है। इस पॉलिसी में AI-बेस्ड उम्र का वेरिफिकेशन, डिजिटल पहचान की जांच, ज्यादा मज़बूत प्राइवैसी सेटिंग्स, पैरेंटल कंट्रोल और अजनबियों के साथ बातचीत पर रोक लगाना ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म को कम उम्र के अकाउंट की पहचान करके उन्हें हटाना होगा। UAE ऐसे पूरे देश में नियम लागू करने वाला पहला अरब देश बन गया है, जो बच्चों और टीनएजर्स में ऑनलाइन सुरक्षा, नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट के संपर्क में आने, स्क्रीन की लत और डिजिटल प्राइवैसी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दिखाता है।
- प्रोफेसर डॉ. बिमल पटेल को समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ITLOS) का न्यायाधीश चुना गया है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कूटनीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत स्थापित, ITLOS एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसका मुख्यालय हैम्बर्ग, जर्मनी में है, जो समुद्री सीमाओं, नेविगेशन अधिकार, मत्स्य पालन, समुद्री संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण और हिरासत में लिए गए जहाजों से संबंधित विवादों को सुलझाता है। पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में कार्य करते हैं। उनका चुनाव वैश्विक समुद्री शासन में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है और नीरू चड्ढा की उपस्थिति को पूरक बनाता है, जो वर्तमान में ITLOS की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं।
- साउथ अटलांटिक आइलैंड सेंट हेलेना पर रहने वाले सेशेल्स के एक बड़े कछुए जोनाथन को ऑफिशियली दुनिया का सबसे पुराना ज़मीन पर रहने वाला जानवर और अब तक का सबसे पुराना कछुआ माना गया है। जोनाथन का जन्म लगभग 1832 में हुआ था, और उनकी उम्र लगभग 194 साल है। अपनी जिंदगी में, उन्होंने विक्टोरियन युग, एफिल टॉवर का बनना, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज का आविष्कार, और कंप्यूटर, इंटरनेट और स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएँ देखी हैं। इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद, जोनाथन काफी हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि उनकी लंबी उम्र का संबंध धीमे मेटाबॉलिज़्म, कम स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल, अच्छे जेनेटिक्स और अच्छे बायोलॉजिकल सिस्टम से है। रिसर्चर हेल्दी एजिंग, लंबी उम्र, सेलुलर रिपेयर और उम्र से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी पाने के लिए उनके DNA की स्टडी कर रहे हैं।

## बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार

- 2022-23 को नया बेस ईयर मानकर एक रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) सीरीज़ शुरू की है, जो पिछली 2011-12 सीरीज़ की जगह लेगी। अपडेटेड फ्रेमवर्क कमोडिटी बास्केट को 697 से बढ़ाकर 957 आइटम करता है और महंगाई मापने में सुधार के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPIs) शुरू करता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे नए सेक्टर शामिल किए गए हैं। यह मॉडर्नाइजेशन भारत के महंगाई ट्रैकिंग सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ जोड़ता है और सामान और सर्विस में प्रोड्यूसर-लेवल प्राइस मूवमेंट के बारे में बेहतर जानकारी देता है।
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने डेज़िग्रेटेड रिपैट्रिएबल रुपया अकाउंट्स शुरू करके NRIs, OCIs और दूसरे विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन को आसान बना दिया है। यह सुधार FEMA रेगुलेशन के तहत इन्वेस्टमेंट ट्रांज़ैक्शन, डिविडेंड रिसीट, सेल प्रोसीड्स और फंड रिपैट्रियेशन को आसान बनाता है। यह कम्प्लायंस रिक्वायरमेंट को भी कम करता है और भारत के बाहर रहने वाले सभी एलिजिबल पर्सन्स रेजिडेंट (PROIs) के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के मौके बढ़ाता है। इस कदम से ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने, कैपिटल मार्केट के गहरा होने और भारत के इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम के मज़बूत होने की उम्मीद है।
- FY27 की शुरुआत में भारत का ट्रेड पैटर्न एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ बढ़ते सरप्लस को दिखाता है, जो सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, तंजानिया और श्रीलंका जैसे मार्केट में मज़बूत एक्सपोर्ट की वजह से है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप जैसे ट्रेडिशनल मार्केट के साथ ट्रेड ज़रूरी बना हुआ है, लेकिन यह बदलाव साउथ-साउथ ट्रेड कोऑपरेशन में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के डायवर्सिफिकेशन को दिखाता है। हालांकि, चीन के साथ बढ़ता ट्रेड डेफिसिट चिंता का विषय बना हुआ है, जिससे इम्पोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है।
- कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) के एक रिव्यू से पता चला है कि FY25 में 28 में से 18 राज्यों ने तय 3% फिस्कल डेफिसिट सीलिंग को पार कर लिया। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और इंटरेस्ट पेमेंट पर बढ़ते खर्च की वजह से कई राज्यों ने सुझाए गए कर्ज़ की लिमिट भी पार कर ली। रिपोर्ट में रेवेन्यू सरप्लस में कमी और बढ़ती उधारी की ज़रूरतों के बारे में चिंता जताई गई है। यह लंबे समय तक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए बेहतर फिस्कल डिसिप्लिन, अच्छे खर्च मैनेजमेंट, सब्सिडी रिफॉर्म और ज़्यादा रेवेन्यू जेनरेशन की ज़रूरत पर ज़ोर देती है।

- सीरीज़ B फंडिंग राउंड में \$234 मिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री कर ली है, जिससे इसकी वैल्यूएशन लगभग \$1.5 बिलियन हो गई है। 2023 में शुरू हुई, बेंगलुरु की यह कंपनी भारत की भाषा और बिज़नेस की ज़रूरतों के हिसाब से साँवरेन AI सॉल्यूशंस बनाती है। यह नया इन्वेस्टमेंट एडवांस्ड AI मॉडल, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज़ AI सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट में मदद करेगा, जिससे भारत का बढ़ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम मज़बूत होगा।
- FY27 की शुरुआत में भारत के ट्रेड पैटर्न से पता चलता है कि सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, तंजानिया और श्रीलंका जैसे एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ सरप्लस बढ़ रहा है। यह बदलाव साउथ-साउथ ट्रेड लिंकेज और अलग-अलग तरह के एक्सपोर्ट मार्केट को दिखाता है। जबकि कुछ यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट मज़बूत बना हुआ है, इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी पर निर्भरता के कारण चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। यह ट्रेड ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ाने के मौकों को दिखाता है, साथ ही घरेलू मैनुफैक्चरिंग को मज़बूत करने और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है।
- एक रिपोर्ट से पता चला है कि FY25 में 18 राज्यों ने GSDP की तय 3% फिस्कल डेफिसिट लिमिट को पार कर लिया। मेघालय, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों में खास तौर पर बहुत ज़्यादा डेफिसिट दर्ज किया गया, जबकि कुल मिलाकर राज्य का कर्ज़ काफी बढ़ गया। सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और इंटरैस्ट पेमेंट पर बढ़ते खर्च के साथ-साथ धीमी रेवेन्यू ग्रोथ ने फिस्कल स्ट्रेस में योगदान दिया। रिपोर्ट में राज्यों में लंबे समय तक फिस्कल सस्टेनेबिलिटी पक्का करने के लिए बेहतर खर्च मैनेजमेंट, सब्सिडी को रेशनलाइज़ करने और रेवेन्यू बढ़ाने के उपायों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है।
- अप्रैल और जून 2026 के बीच भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन साल-दर-साल 14.64% बढ़कर ₹ 5.21 ट्रिलियन हो गया। ग्रोथ मज़बूत कॉर्पोरेट टैक्स और नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की वजह से हुई, जो बेहतर कम्प्लायंस, ज़्यादा एडवांस टैक्स पेमेंट और मज़बूत इकोनॉमिक एक्टिविटी को दिखाता है। ग्रॉस कलेक्शन ₹ 6.1 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जबकि रिफंड भी बढ़ा। मज़बूत टैक्स परफॉर्मेंस से पता चलता है कि इकोनॉमिक फॉर्मलाइज़ेशन जारी है, बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर एफिशिएंसी है।
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने कर्नाटक में श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस उसकी खराब फाइनेंशियल हालत, काफ़ी कैपिटल और डिपॉज़िटर्स को पैसे न चुका पाने की वजह से कैंसिल कर दिया है। बैंक को बैंकिंग ऑपरेशन बंद करने का निर्देश दिया गया है,

जबकि एक लिक्विडिटर बैंक बंद करने की कार्रवाई की देखरेख करेगा। DICGC इश्योरेंस के तहत, लगभग 97.9% डिपॉज़िटर्स को ₹ 5 लाख की इश्योर्ड लिमिट तक पूरा पेमेंट मिलने की उम्मीद है। इस फ़ैसले का मकसद डिपॉज़िटर्स की सुरक्षा करना और बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बनाए रखना है।

- RBI ने HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर केकी मिश्री को सितंबर 2026 तक या परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट होने तक तीन महीने का एक्सटेंशन देने की मंजूरी दी है। यह एक्सटेंशन पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद बदलाव के दौरान लीडरशिप कंटिन्यूटी पक्का करता है। मिश्री के लगातार रोल से गवर्नेंस में स्टेबिलिटी आने और परमानेंट उत्तराधिकारी के सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान बैंक की स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

### नियुक्तियाँ/इस्तीफ़े

- कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी ने हितेश जोशी को जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) अपॉइंट किया है। एक अनुभवी इश्योरेंस प्रोफेशनल और इश्योरेंस इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के फेलो, वे रीइश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट हैं। उनके अपॉइंटमेंट से GIC Re की लीडरशिप मज़बूत होने और भारत के इश्योरेंस और रीइश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- सुंदरराज पट्टिलिंगम को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में एंटी-नक्सल ऑपरेशन्स में अपने बहुत ज़्यादा अनुभव के लिए जाने जाने वाले सुंदरराज ने माओवादी विद्रोह के खिलाफ सुरक्षा ऑपरेशन्स को कोऑर्डिनेट करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके अपॉइंटमेंट से NIA की काउंटर-टेररिज्म और नेशनल सिक्वोरिटी क्षमताओं को और मज़बूती मिलने की उम्मीद है।
- बाटा इंडिया ने गुंजन शाह की जगह संजय राव को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया है। नाइकी में लीडरशिप रोल और ज़ारा इंडिया को बढ़ाने में शामिल होने सहित दो दशकों से ज़्यादा के इंटरनेशनल रिटेल अनुभव के साथ, राव रिटेल ग्रोथ, कंज्यूमर एंगेजमेंट और ब्रांड मैनेजमेंट में एक्सपर्टिज़ लाते हैं। उनके अपॉइंटमेंट से इनोवेशन को सपोर्ट मिलने, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और बाटा इंडिया की लॉन्ग-टर्म एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के उपाध्यक्ष के रूप में विवेक अग्रवाल के चुनाव के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिससे वे इस प्रभावशाली पद को धारण करने वाले पहले भारतीय बन गए। पेरिस में FATF प्लेनरी मीटिंग में चुने गए, वे जुलाई 2026 से जून 2027 तक काम करेंगे। मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी, अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें वित्तीय खुफिया और नियामक मामलों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पहले FIU-IND के निदेशक, वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और भारत के FATF प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में कार्य किया। 1989 में स्थापित, FATF मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और उभरते वित्तीय खतरों से निपटने के लिए वैश्विक मानक विकसित करता है,

### रक्षा समाचार

- जेंडर इन्क्लूजन की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए, 17 महिला NDA कैडेट्स के पहले बैच को मेल कैडेट्स के साथ कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जून 2026 में ऑफिसर्स के तौर पर कमीशन किया गया। इनमें से 9 इंडियन आर्मी में, 5 इंडियन एयर फोर्स में और 3 इंडियन नेवी में शामिल हुईं। 2022 में नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में शामिल होने के बाद, कैडेट्स ने उन्हीं ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स और लीडरशिप प्रोग्राम्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मील का पत्थर भारत के इक्वालिटी, मेरिट-बेस्ड सिलेक्शन और अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन के कमिटमेंट को दिखाता है।
- डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने 15 जून 2026 को ओडिशा के डॉ. APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक कूज़ मिसाइल (LRLACM) का सफल फ्लाइंग-टेस्ट किया। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डेवलप की गई इस मिसाइल को लंबी दूरी पर स्ट्रेटिजिक ज़मीनी टारगेट पर बहुत सटीकता से हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के उलट, यह कम ऊंचाई वाले गाइडेड फ्लाइंग पाथ को फ़ॉलो करती है, जिससे पता लगाना और इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाता है। यह सफल ट्रायल भारत की लॉन्ग-रेंज प्रिसिज़न स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी को मज़बूत करता है, और मॉडर्न युद्ध में कूज़ मिसाइलों की बढ़ती भूमिका को दिखाता है।
- इंडियन नेवी ने अर्नाला-क्लास एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) के पांचवें वेसल INS अग्रे को शामिल किया। प्रोग्राम। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का बनाया हुआ यह जहाज़ हल-माउंटेड सोनार, वेरिबल डेपथ सोनार (VDS), एंटी-सबमरीन टॉरपीडो और रॉकेट से लैस है। 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री वाला, INS अग्रे आत्मनिर्भर भारत मिशन को सपोर्ट करता है और तटीय निगरानी, माइन वॉरफेयर और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन को बढ़ाता है। इसके शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में रणनीतिक मौजूदगी मज़बूत होती है।
- इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक्सरसाइज़ पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लेगी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स की होस्ट की हुई इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज़ में 19 देशों के 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और लोग शामिल होंगे। यह इवेंट एडवांस्ड एयर कॉम्बैट ऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, टैक्टिकल इंटीग्रेशन और मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन पर फोकस करेगा। इसमें हिस्सा लेने से पार्टनर देशों के साथ भारत का डिफेंस कोऑपरेशन मज़बूत होगा और मुश्किल कॉम्बैट माहौल में ऑपरेशनल तैयारी बढ़ेगी।
- 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक मंगोलिया के उलानबटार में होने वाली एक्सरसाइज़ खान क्रेस्ट 2026 में हिस्सा लेगी। यह मल्टीनेशनल एक्सरसाइज़ यूनाइटेड नेशंस के पीसकीपिंग ऑपरेशन्स पर फोकस करती है, जिसमें जॉइंट प्लानिंग, पेट्रोलिंग, सिविलियन इवैक्युएशन, काउंटर-IED ड्रिल्स और कैजुअल्टी इवैक्युएशन शामिल हैं। इसमें हिस्सा लेने से पार्टनर सेनाओं के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है और ग्लोबल पीसकीपिंग और इंटरनेशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए भारत का कमिटमेंट दिखता है।
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट के मरीन गैस टरबाइन जनरेटर (MG TG) के 12 सेटों की खरीद के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ ₹ 425 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित यह अनुबंध खरीदें (भारतीय) श्रेणी के अंतर्गत आता है और 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री को अनिवार्य करता है। MG TG महत्वपूर्ण ऑनबोर्ड बिजली उत्पादन प्रणाली हैं जो प्रबंधन प्रणालियों, रडार और निगरानी उपकरण, संचार नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत हथियार प्लेटफार्मों को बिजली प्रदान करते हैं। यह परियोजना सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों का समर्थन करती है

- भारत ने 18 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में पहले स्वदेश निर्मित एयर कुशन वाहन (ACV) H-561 को शामिल करने के साथ समुद्री रक्षा में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की। गोवा में चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित, होवरक्राफ्ट तटरक्षक बल द्वारा आदेशित यह ACV में से पहला है। पारंपरिक जहाजों के विपरीत, यह शक्तिशाली लिफ्ट प्रशंसकों द्वारा उत्पन्न हवा के कुशन पर चलता है, जिससे उथले पानी, कीचड़, दलदली भूमि, रेतीले समुद्र तटों, मुहाना और आर्द्रभूमि पर आवाजाही संभव हो जाती है। यह क्षमता इसे भारत के 7,500 किलोमीटर के समुद्र तट को सुरक्षित करने के लिए आदर्श बनाती है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित, H-561 भारत की बढ़ती स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए तटीय निगरानी, तीव्र प्रतिक्रिया संचालन और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा।
- भारतीय नौसेना तीन स्वदेश निर्मित युद्धपोतों - आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रे और आईएनएस संशोधक को 21 जून 2026 को कोलकाता में कमीशन करेगी। भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा निर्मित ये जहाज रक्षा निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईएनएस दूनागिरी, एक प्रोजेक्ट 17ए स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, सतह, हवा और पनडुब्बी रोधी युद्ध में सक्षम है और ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर सकता है। आईएनएस अग्रे पानी के नीचे खतरे का पता लगाने के लिए उन्नत सोनार सिस्टम, टॉरपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस है। आईएनएस संशोधक, संधायक -क्लास कार्यक्रम का अंतिम पोत, स्वायत्त पानी के नीचे के वाहनों (एयूवी) और दूर से संचालित वाहनों (आरओवी) का उपयोग करके हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, सीबेड मैपिंग और पानी के नीचे डेटा संग्रह के लिए डिजाइन किया गया है।

### पुरस्कार और सम्मान

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रातिस्लावा के अपने दौर के दौरान स्लोवाक प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी से मशहूर ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) मिला। यह सम्मान भारत-स्लोवाकिया रिश्तों को मजबूत करने और इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देने में उनके योगदान को पहचान देता है। यह किसी दूसरे देश की तरफ़ से PM मोदी को दिया गया 33वां इंटरनेशनल सम्मान था, जो भारत के बढ़ते डिप्लोमैटिक असर और ग्लोबल जुड़ाव को दिखाता है।

- नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को मशहूर प्रिक्स वर्सेल्स वल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स लिस्ट 2026 में शामिल किया गया। यह पहचान बेहतरीन आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए दी गई। नवी मुंबई एयरपोर्ट ने अपने लोटस-इंस्पायर्ड डिज़ाइन से सबको इम्प्रेस किया, जबकि गुवाहाटी टर्मिनल को इसके बैम्बू ऑर्किड-इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर के लिए पहचान मिली, जो नॉर्थईस्ट इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। यह अचीवमेंट वर्ल्ड-क्लास, एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के बढ़ते फोकस को दिखाता है।
- भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जैनेंद्र के. जैन भौतिकी में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने। उन्हें संमिश्र फर्मिऑन की अग्रणी खोज के लिए यह पुरस्कार मिला, जिसने आंशिक क्वांटम हॉल प्रभाव की समझ को बदल दिया। यह पुरस्कार येरुशलम में इसाक हर्ज़ॉग द्वारा प्रदान किया गया था। 1989 में, येल विश्वविद्यालय में रहते हुए, जैन ने प्रस्ताव दिया कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम भंवर के साथ मिलकर संमिश्र फर्मिऑन बना सकते हैं, जो पहले से अस्पष्टीकृत आंशिक चालकता स्थितियों के लिए एक एकीकृत स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उनके सिद्धांत ने प्रसिद्ध "जैन राज्यों" की भविष्यवाणी की और संघनित पदार्थ भौतिकी की आधारशिला बन गया। राजस्थान के सांभर में जन्मे, उन्होंने आईआईटी कानपुर में अध्ययन किया, स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।

### खेल समाचार

- सात बार के फ़ॉर्मूला वन चैंपियन लुईस हैमिल्टन ने बार्सिलोना-कैटालुन्या ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्कुडेरिया फ़रारी के लिए अपनी पहली जीत हासिल की, जिससे मर्सिडीज़ का हालिया दबदबा खत्म हो गया। हैमिल्टन ने जॉर्ज रसेल से आगे रहने के लिए एक सफल थ्री-स्टॉप स्ट्रैटेजी अपनाई, जबकि लैंडो नॉरिस ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे 1968 के बाद पहला ऑल-ब्रिटिश पोडियम बना। चैंपियनशिप के दावेदार किमी एंटोनेली टेक्निकल दिक्कतों की वजह से देर से रिटायर हुए, जिससे टाइल की रेस और तेज़ हो गई। यह नतीजा फ़रारी की वापसी को दिखाता है और हैमिल्टन के चैंपियनशिप कैम्पेन को और तेज़ी देता है।

- केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नर्स (NSG) एक्ट, 2025 के तहत एक सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी बनाई है, जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए कैंडिडेट रिकमेंड करेगी। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में जाने-माने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। प्रस्तावित बोर्ड भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स गवर्नर्स रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा, जो स्पोर्ट्स फेडरेशन, गवर्नर्स स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करेगा। यह पहल देश में ज्यादा ट्रांसपेरेंट, प्रोफेशनल और अकाउंटेबल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- स्मृति मंधाना TIME100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट बन गईं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए पहचानी जाने वाली, वह तीनों फॉर्मेट— टेस्ट, ODI और T20I में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मंधाना महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी शेयर करती हैं और उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी की कप्तान के तौर पर काफी सफलता हासिल की है। उनका शामिल होना महिला क्रिकेट के बढ़ते ग्लोबल प्रभाव और इस खेल में भारत की प्रमुखता को दिखाता है।
- दीप्ति शर्मा ने ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपना 355वां इंटरनेशनल विकेट लेकर विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब वह झूलन गोस्वामी और कैथरीन साइबर-ब्रंट के साथ यह रिकॉर्ड शेयर करती हैं। यह उपलब्धि दीप्ति की कंसिस्टेंसी, लंबे समय तक खेलने और भारतीय क्रिकेट के लिए उनके महत्व को दिखाती है, जिससे विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की बढ़ती रेप्युटेशन और मजबूत होती है।
- ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के साथ मिलकर डोपिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए क्लीन स्पोर्ट्स कैम्पेन शुरू किया। इस पहल में एथलीट के नेतृत्व में आउटरीच, वर्कशॉप, डिजिटल एजुकेशन टूल और जमीनी स्तर के प्रोग्राम शामिल हैं। इसका मकसद एथलीटों को बैन की गई चीजों के बारे में जानकारी देना, नैतिक खेल के तरीकों को बढ़ावा देना और भारत की खेल में पहचान को मजबूत करना है, खासकर तब जब देश 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- भारत की तेज़ी से बढ़ती स्पेस इकॉनमी के अगले दशक में अभी के USD 8-9 बिलियन से बढ़कर लगभग USD 40-45 बिलियन होने का अनुमान है। RISE कॉन्क्लेव 2026 में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिबरलाइजेशन सुधारों और सैटेलाइट, लॉन्च सिस्टम, AI-बेस्ड जियोस्पेशियल एनालिटिक्स और डाउनस्ट्रीम सर्विसेज़ में इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स की भूमिका पर ज़ोर दिया। चंद्रयान-3 और आने वाले गगनयान मिशन जैसे बड़े मिशनों ने भारत की ग्लोबल स्थिति को मजबूत किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी PM गति शक्ति जैसे गवर्नर्स इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट कर रही है, जो विकसित भारत 2047 के विज़न में योगदान दे रही है।
- फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने Kali365 के बारे में चेतावनी दी है, जो एक एडवांस्ड फिशिंग-एज-ए-सर्विस ( PhaaS ) प्लेटफॉर्म है और माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर्स को टारगेट करता है। पासवर्ड चुराने के बजाय, यह प्लेटफॉर्म डिवाइस-कोड ऑथेंटिकेशन अटैक के जरिए OAuth टोकन कैप्चर करता है, जिससे अटैकर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को बायपास कर सकते हैं और अकाउंट एक्सेस बनाए रख सकते हैं। Kali365 AI से जेनरेटेड फिशिंग टेम्प्लेट, ऑटोमेटेड टूल और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड देता है, जिससे कम स्किल वाले क्रिमिनल्स के लिए एडवांस्ड साइबर अटैक एक्सेसिबल हो जाते हैं। यह खतरा क्लाउड-बेस्ड सिस्टम में आइडेंटिटी सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की बढ़ती इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (IIT बॉम्बे) के नेतृत्व में, भारत ने इंडियाएआई मिशन के तहत एक संप्रभु बहुभाषी AI पारिस्थितिकी तंत्र भारतजेन को लॉन्च किया है। ₹ 10,000 करोड़ की सरकारी पहल द्वारा समर्थित, भारतजेन को सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में सामग्री को समझने और उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-स्पीच, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस और बहुभाषी सामग्री निर्माण जैसी क्षमताओं को एकीकृत करता है। विदेशी AI प्रणालियों पर निर्भरता कम करके, भारतजेन डिजिटल संप्रभुता का समर्थन करता है, स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देता है, और शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और सार्वजनिक सेवाओं में AI अनुप्रयोगों को सक्षम बनाता है।

- उसुतु वायरस (USUV) , जो वेस्ट नाइल वायरस और जापानी एन्सेफलाइटिस से जुड़ा एक मच्छर से फैलने वाला फ्लेविवायरस है, पहली बार स्कॉटलैंड में पाया गया है। आइल ऑफ़ एरन पर ब्लैकबर्ड्स में पाया जाने वाला यह वायरस मुख्य रूप से जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है और पक्षियों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और मौत का कारण बन सकता है। इंसानों में इसके इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं और आमतौर पर हल्के होते हैं। यह खोज बदलते पर्यावरण और इकोलॉजिकल हालात में वन्यजीवों की निगरानी और उभरती हुई जूनोटिक बीमारियों की मॉनिटरिंग के महत्व को दिखाती है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक उन्नत चंद्र लैंडर विकसित कर रहा है जो चंद्रमा पर 100-200 दिनों तक जीवित रह सकता है, जो चंद्रयान -3 के विक्रम लैंडर से काफी अधिक लंबा है। परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के सहयोग से विकसित , लैंडर -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के चरम चंद्र-रात्रि तापमान का सामना करने के लिए उन्नत थर्मल प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करेगा। परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दीर्घकालिक वैज्ञानिक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना है, जिसमें जल बर्फ और चंद्र भूविज्ञान पर अनुसंधान शामिल है। यह भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 का समर्थन करता है , जिसमें 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना शामिल है

### महत्वपूर्ण दिन

- 15 जून को मनाया जाने वाला ग्लोबल विंड डे 2026 , “विंड एनर्जी: एम्बिशन से एक्सेलरेशन तक” थीम के तहत मनाया जा रहा है। भारत ऑनशोर विंड , ऑफशोर विंड , घरेलू मैनुफैक्चरिंग और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के ज़रिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। देश की इंस्टॉलड विंड पावर कैपेसिटी 2014 में 21.04 GW से बढ़कर 2026 में 56.09 GW हो गई है , जिससे भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। 1,163.9 GW की अनुमानित क्षमता , गुजरात और तमिलनाडु में चल रहे ऑफशोर प्रोजेक्ट्स और बढ़ते स्वदेशीकरण के साथ , भारत अपने बड़े 100 GW विंड एनर्जी कैपेसिटी टारगेट की ओर लगातार बढ़ रहा है।
- मगरमच्छों और उनसे जुड़ी प्रजातियों जैसे घड़ियाल , एलीगेटर और कैमन के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है। 2026 की थीम, “हर पैमाने में

विरासत,” मगरमच्छों के विकास के महत्व और उनके आवासों की रक्षा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देती है। सबसे बड़े शिकारी होने के नाते, मगरमच्छ पानी के इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत को क्रोकोडाइल कंज़र्वेशन प्रोजेक्ट (1975) जैसी पहलों और भीतरकनिका नेशनल पार्क और नेशनल चंबल सैंक्चुअरी जैसे सुरक्षित क्षेत्रों के ज़रिए दुनिया भर में संरक्षण की सफलता की कहानी माना जाता है, जो मगर मगरमच्छ , खारे पानी के मगरमच्छ और घड़ियाल की सुरक्षा करते हैं।

- ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून 2026 को दुनिया भर में “रिकग्निशन, रिप्रेजेंटेशन, और रिफॉर्म” थीम के तहत मनाया गया। यह दिन ऑटिस्टिक लोगों के लिए न्यूरोडायवर्सिटी , इनक्लूजन और समान अवसरों को बढ़ावा देता है। पहली बार 2005 में मनाया गया यह दिन समाज को ऑटिज़्म को इंसानी न्यूरोलॉजी के एक नैचुरल रूप के रूप में पहचानने के लिए बढ़ावा देता है, साथ ही शिक्षा, हेल्थकेयर, नौकरी और पब्लिक पार्टिसिपेशन तक बेहतर पहुंच की वकालत करता है। रेनबो इनफिनिटी सिंबल ऑटिस्टिक समुदायों की डायवर्सिटी और ताकत को दिखाता रहता है।
- हर साल 17 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2026 का थीम था “रेंजलैंड्स: पहचानो। सम्मान करो। बहाल करो।” इस दिन बायोडायवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंस को सपोर्ट करने में घास के मैदानों , सवाना , झाड़ियों और दूसरे रेंजलैंड इकोसिस्टम के महत्व पर ज़ोर दिया गया। भारत में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2.0 के तहत 813 प्रोजेक्ट एरिया में जागरूकता और बहाली की गतिविधियाँ की गईं , जिससे सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को बढ़ावा मिला।

**Test Prime**

ALL EXAMS  
ONE SUBSCRIPTION

IBPS

- 19 जून को मनाया जाने वाला **वर्ल्ड सिकल सेल डे 2026**, "क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप: इक्विटी इन सिकल सेल डिज़ीज़" थीम पर फोकस करता है। यह दिन सिकल सेल डिज़ीज़ (SCD) के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है, जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से होने वाला एक हेरेडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है। भारत नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपेन और जेनेटिक काउंसलिंग इनिशिएटिव के ज़रिए 2047 तक SCD को एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज के तौर पर खत्म करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं, खासकर उन ट्राइबल पॉपुलेशन को टारगेट करके जहाँ यह बीमारी आम है।
- वर्ल्ड रिफ्यूजी डे** हर साल 20 जून को उन लाखों लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो लड़ाई, जुल्म, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन की वजह से बेघर हो गए हैं। 2026 की थीम, "जब तक हर कोई सुरक्षित न हो," इस बात पर ज़ोर देती है कि सुरक्षा में कानूनी सुरक्षा, रहने की जगह, हेल्थकेयर, शिक्षा, रोज़गार, सामाजिक समावेश और सम्मान शामिल हैं। 2000 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा शुरू किया गया यह दिन शरणार्थियों की चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के वादे को मज़बूत करता है। यह शरणार्थियों की हिम्मत को पहचानता है और मानवीय मदद, समावेश और सुरक्षा और सम्मान के साथ ज़िंदगी फिर से बनाने के मौकों को बढ़ावा देता है।

### स्टेटिक टेकअवे

पहलू	विवरण
बिहार	CM: सम्राट चौधरी, गवर्नर: आरिफ खान, राजधानी: पटना
झारखंड	CM: हेमंत सोरेन, गवर्नर: संतोष गंगवार, राजधानी: रांची
केरल	मुख्यमंत्री: वीडी सतीशन, गवर्नर: आर आर्लेकर, राजधानी: तिरुवनंतपुरम
ओडिशा	CM: मोहन माझी, गवर्नर: हरिबाबू खंभापति, राजधानी: भुवनेश्वर
असम	CM: हिमंत सरमा, गवर्नर: लक्ष्मण आचार्य, राजधानी: दिसपुर
कर्नाटक	CM: डीके शिवकुमार, गवर्नर: थावर चंद गहलोत, राजधानी: बेंगलुरु
महाराष्ट्र	CM: देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर: जिष्णु देव वर्मा, राजधानी: मुंबई
आंध्र प्रदेश	CM: चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर: अब्दुल नज़ीर, राजधानी: अमरावती
मध्य प्रदेश	CM: मोहन यादव, गवर्नर: मंगूभाई पटेल, राजधानी: भोपाल
मेघालय	CM: कोनराड संगमा, गवर्नर: सीएच विजयशंकर, राजधानी: शिलांग
तमिलनाडु	CM: जोसेफ विजय, गवर्नर: आर आर्लेकर, राजधानी: चेन्नई
फ्रांस	राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रों
इंग्लैंड	प्रधानमंत्री: कीर स्टारमर
संयुक्त राज्य अमेरिका	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प
जर्मनी	चांसलर: फ्रेडरिक मर्ज़
इटली	प्रधानमंत्री: जॉर्जिया मेलोनी
भारतीय रिज़र्व बैंक	अध्यक्ष: संजय मल्होत्रा
सेबी	चेयर पर्सन : तुहिन कांता पांडे